

वाइस ऑफ प्रतिज्ञा

जब्बा सच दिखाने का

वर्ष -06

अंक -85

मूल्य: 2.00 ₹.

अलवर, रविवार 07 जून 2026

प्रभात संस्करण

कुल पेज- 8

WWW.Voiceofpratigya.com | Twitter.com/Voiceofpratigya | facebook.com/Voiceofpratigya | YouTube.com/Voiceofpratigya | Instagram- Instagram.com/Voiceofpratigya | 9414508610 | pratigya.alwar@gmail.com

यह लड़ाई लंबी, हम पीछे हटने वाले नहीं: जंतर-मंतर से बोले अभिजीत दीपके, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा

वाइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को कांक्रोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुटे। इस दौरान सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी है और छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी जैसी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच हुआ यह प्रदर्शन पूरे दिन चर्चा का केंद्र बना रहा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि पिछले एक महीने से सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय आंदोलन को दबाने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पोस्ट हटवाने और अकाउंट हक कराने की कोशिश



की गई। दीपके ने मंच से कहा, 'आप हमारी पोस्ट हटा सकते हैं, लेकिन हमें इस जगह से मिटा नहीं सकते। उनके इस बयान पर प्रदर्शन स्थल पर मौजूद युवाओं ने जोरदार नारेबाजी की। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ बड़ी संख्या में युवा पेशेवर भी पहुंचे। कई प्रदर्शनकारी कांक्रोच मास्क पहने दिखाई दिए। कुछ लोग हाथों में फूल और तिरंगा लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे' और 'मेक इन इंडिया नहीं, लोक इन इंडिया' जैसे नारे लगाए। कई छात्र अपने अभिभावकों के साथ भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह राजनीतिक और छात्र आंदोलनों जैसा नजर आया। अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन शुरू होने से पहले समर्थकों से साफ कहा था कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहना चाहिए। उन्होंने लोगों से फिक्ताब और तिरंगा लेकर आने की अपील की थी। साथ ही पुलिसकर्मियों को सम्मान के तौर पर फूल देने की बात भी कही। दीपके ने कहा कि यह आंदोलन ध्यार और शांति के रास्ते पर

चलेगा। प्रदर्शन से पहले सीजेपी ने सोशल मीडिया पर दिशा-निर्देश भी जारी किए थे, जिसमें किसी तरह के टकराव से बचने को कहा गया था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। अभिजीत दीपके ने मंच से उनका धन्यवाद किया और कहा कि वह जल्द प्रदर्शन में शामिल होंगे। वांगचुक ने कहा है कि अगर अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया गया तो वह छह सप्ताह का उपवास करेंगे। इससे आंदोलन को और ज्यादा चर्चा मिली है। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने कहा कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जरूरी है और छात्रों की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी थी। जंतर-मंतर, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया। पुलिस ने सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक प्रदर्शन की अनुमति

दी थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए रही। कांक्रोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक युवा आंदोलन है, जो परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही की मांग कर रहा है। हाल के महीनों में नीट और अन्य परीक्षाओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे में सीजेपी का यह आंदोलन युवाओं के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह आंदोलन आगे और तेज हो सकता है। अभिजीत दीपके ने कहा कि छात्र और युवा पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं आती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल दिल्ली का जंतर-मंतर छात्रों के गुस्से और सरकार से जवाब मांगने का बड़ा मंच बन गया है।

भारत में घटती जन्म दर पर एलन मस्क ने जताई चिंता, रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंचा आंकड़ा



वाइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूयॉर्क

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भारत की घटती जन्म दर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत की जन्म दर अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंच चुकी है, जो लंबे समय में जनसंख्या संरचना पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट को साझा करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत की जन्म दर कई साल पहले ही शिक्षित वर्ग में रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुकी है। मस्क ने जिस डेटा का हवाला दिया, उसमें कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर लगभग 1.9 पर आ गई है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में फर्टिलिटी रेट घटकर करीब 1.2 तक पहुंच गई है, जो कई विकसित देशों से भी कम मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, जीवनशैली और आर्थिक कारणों से परिवार का आकार लगातार छोटा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 में भी बताया गया है कि भारत की फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे गिरकर 1.9 पर आ चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो रही है। भारत की आबादी वर्तमान में 1.46 अरब से अधिक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दशकों में घटती जन्म दर देश की आर्थिक संरचना, श्रम बाजार और सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है, लेकिन असमानता, बाल विवाह और महिलाओं से जुड़ी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं।

न्यायपालिका को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर एआईबीए सख्त, कहा- इससे घटती है संस्थानों की गरिमा

वाइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणी पर देश की कानूनी बिरादरी में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने उनके बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे जिम्मेदारीहीन, क्षामक और संस्थागत गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। एआईबीए के अध्यक्ष आदित्य शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधी का बयान देश की न्यायपालिका की साख और विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, जो अत्यंत गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण और पवित्र संस्थान है, जो कानून के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ऐसे में किसी भी तरह के सामान्यीकृत आरोप न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं। अग्रवाल ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण दुनिया भर में सम्मान अर्जित किया है। ऐसे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी को न्यायधीनता को निष्पक्षता पर संदेह पैदा करे, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है।

गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने, खेल मैदान विकसित करने की घोषणा: सीएम

खारी का लाम्बा गांव में मुख्यमंत्री का प्रातः भ्रमण

जनसंवाद और सौगातों का बना माध्यम

युवाओं के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और

वाइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लाम्बा गांव में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को प्रातः भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गांव के बुजुर्गों जिनमें विशेषकर 107 वर्ष की कुमकुम देवी और 102 वर्ष के ओंकार तेली से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य, दिनचर्या एवं जीवन के अनुभवों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री का अपनाने देखकर बुजुर्गों ने भी उनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान घर-घर जाकर ग्रामीणों से



हालचाल जाने। साथ ही, बच्चों को दुलार करते हुए उन्हें चॉकलेट वितरित की। उन्होंने गांव के रघुनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए। वहीं, फूलसागर तालाब किनारे योग कर रहे युवाओं के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने श्रमदान के साथ तालाब के सौंदर्यकरण करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्होंने शीशम का वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए गांव की आवश्यकताओं और विकास कार्यों पर विस्तार से बातचीत की।

वहीं, ग्रामीणों की मांगों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने तथा खेल मैदान विकसित करने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि खारी का लाम्बा गांव में शुक्रवार रात आयोजित ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नए कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय की स्थापना, कृषि पर्यवेक्षक पद के सृजन तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त संकाय विज्ञान (जीव विज्ञान) एवं कृषि विज्ञान प्रारंभ करने के आदेश शनिवार सुबह ग्रामीणों को मिले। घोषणाओं के



शीघ्र क्रियान्वयन पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही, उन्होंने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गांव में रात्रि विश्राम कर न केवल उनकी समस्याएं सुनीं, बल्कि उनके समाधान की दिशा में तत्काल कदम भी उठाए। मुख्यमंत्री के जनसंवाद और संवेदनशील कार्यशैली की ग्रामीणों ने जन्मकर साराहना की। इस दौरान प्रातः भ्रमण और जनसंवाद में उप-मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैवा, विधायक जयबंकर सिंह सांखला, लाला राम बैरवा, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

जो कोर्ट-कचहरी का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए भी सुलभ हो अदालत: चीफ जस्टिस सूर्यकांत

वाइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ऐसा न्यायालय जो केवल उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है जो मुकदमेबाजी का खर्च उठाने में सक्षम हैं, वह अपने संवैधानिक कार्य को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि केवल उसकी ओपचारिकता निभा रहा है। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका को न केवल अधिकारों का संरक्षक होना चाहिए, बल्कि 'यह इतनी सुलभ होनी चाहिए कि उसका संरक्षण वास्तविक रूप से महसूस हो'। जस्टिस सूर्यकांत 'नवीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन' में वाणिज्यिक विधि केंद्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गये थे। उन्होंने छात्रों के साथ व्यापक चर्चा की और छात्रों ने उनसे न्यायपालिका, न्याय तक पहुंच और कानूनी पेशे के भविष्य समेत विभिन्न मुद्दों पर कई सवाल पूछे। संवैधानिक लोकतंत्र में जनता के भरोसे को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जनता का भरोसा किसी संस्था को यूं ही नहीं



मिल जाता, बल्कि इसे पारदर्शिता, निरंतरता और आत्म-सुधार के जरिये लगातार हासिल करना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका जवाबदेही की अंतिम कड़ी है, लेकिन उसे स्वयं संविधान और उन लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जिनके लिए यह अस्तित्व में है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने एक समान राष्ट्रीय न्यायिक नीति पर जोर दिया है। जब अदालतों के फैसले सुसंगत होते हैं, तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता है। इससे नागरिकों को यह समझने में आसानी होती है कि कानून कैसे लागू होगा और वे उसी के अनुसार अपने निर्णय ले सकते हैं। यही

कानून के शासन का मूल सिद्धांत है। आधुनिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूछे जाने पर, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका का सर्वोपरि कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान में निहित सिद्धांत केवल कागज पर लिखे शब्द न हों, बल्कि इस बात की गारंटी बने जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, विशेष रूप से उन लोगों को, जो हाशिये पर हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के अत्याचार या उनके अधिकारों के हनन से बचाया जा सके। अदालतों के भविष्य और समय पर उचित उपचार मिल सके। विगत ढाई वर्षों में, इस बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान न्याय तक पहुंच का विस्तार करने में रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका के समक्ष चुनौती यह है कि वह निष्पक्षता, सुलभता और सभी के लिए समान न्याय की संवैधानिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए नवाचार को अपनाए।

अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार के लिए निर्देश, विभाग की ओपीडी में ही दवा काउंटर की व्यवस्था हो सुनिश्चित

वाइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सर्वाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर ओपीडी सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की ओपीडी में चिकित्सा व्यवस्थाओं, दवाओं, जांच सहित साफ-सफाई के संबंध में अस्पताल प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली। साथ ही, उन्होंने रोगियों एवं उनके परिजनों से आत्मीयता से बातचीत की तथा उनसे मिले फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भीलवाड़ा दौरे से जयपुर वापसी पर

ही जांच और दवा काउंटर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं, उन्होंने अस्पताल परिसर में रोगियों और उनके परिजनों के लिए बैठने एवं पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ ही साफ-सफाई रखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार सर्वाई मानसिंह अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बना रही है, जिससे यहां मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। विगत ढाई वर्षों में एसएमएस में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। इसके लिए चिकित्सा विभाग एवं अस्पताल प्रशासन साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जहां भी सुधार की गुंजाइश है, वहां जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

ही जांच और दवा काउंटर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं, उन्होंने अस्पताल परिसर में रोगियों और उनके परिजनों के लिए बैठने एवं पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ ही साफ-सफाई रखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार सर्वाई मानसिंह अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बना रही है, जिससे यहां मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। विगत ढाई वर्षों में एसएमएस में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। इसके लिए चिकित्सा विभाग एवं अस्पताल प्रशासन साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जहां भी सुधार की गुंजाइश है, वहां जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

मानसून की चाल से बदला मौसम: कहीं बरस रहे बादल तो कहीं तप रही धरती



वाइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेजी से आगे बढ़ने के साथ देश का मौसम अब स्पष्ट रूप से दो अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के कई इलाकों में गर्मी अभी भी अपना प्रभाव बनाए हुए है। हालांकि, रविवार से उत्तर भारत के पहाड़ी से लेकर मेदानी राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं, गरज-चमक और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और पूर्वोत्तर भारत के अतिरिक्त हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने और कुछ जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। केरल और माहे में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर 204.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जम्मू-कश्मीर-ल्हाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फरबाद में 7 से 12 जून के दौरान छिटपुट वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 11-12 जून तक हल्की से भारी बारिश हो सकती है। उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और कुछ मेदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली-एनसीआर, पूर्व व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान में भी 12 जून तक अलग-अलग स्थानों पर छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

तीन महीने में दूसरी बार महंगा हुआ घरेलू सिलिंडर, रसाई गैस में 29 रुपये बड़े

वाइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, घरेलू रसाई गैस (एलपीजी) सिलिंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें 7 जून यानी आज से लागू हो गई हैं। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो जाएगी। यह पिछले तीन महीनों में दूसरी बार है जब घरेलू गैस सिलिंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलिंडर 60 रुपये की वृद्धि की गई थी। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मार्च में की गई 60 रुपये की वृद्धि के बावजूद तेल निरपन कर्पणियों को घरेलू एलपीजी बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। ताजा संशोधन से पहले सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था। ऐसे में बढ़ती लागत को देखते हुए कीमतों में इजाजत करना आवश्यक माना गया। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल मिलाकर 7.50 प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं, जबकि CNG प्रति किलो महंगा हुई है।

खरगे जी का अधूरा ज्ञान खतरनाक है: कांग्रेस अध्यक्ष पर भड़के जेपी नड्डा, बोले- देश का भला तथ्यों से होता है

वाइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के स्वास्थ्य से जुड़े डेटा छिपाने के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। नड्डा ने कहा है कि जनता का स्वास्थ्य राजनीतिक बयानबाजियों तक सिमटने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए यहां तक कहा है अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। दरअसल, पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें महिलाओं और बच्चों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। दावे में 2023-24 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 के कुछ कथित आंकड़ों का हवाला दिया गया। इसी आधार पर खरगे ने कहा कि मोदी सरकार इसके आंकड़े छिपा रही है, क्योंकि इससे इसकी नाकाम उजागर हो गई है। इसी पर जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खरगे के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उनपर पलटवार किया।

सम्पादकीय

अग्निकांड: मौत के बाद जांच, जांच के बाद खामोशी



कि सी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक यह होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं, ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। मगर ऐसा लगता है कि आए दिन इमारतों में आग लगने और उसमें लोगों की जान जाने की घटनाओं से कोई सबक नहीं लेने की लापरवाही एक सामान्य चलन बन चुकी है। राजधानी दिल्ली में एक इमारत में आग लगने की वजह से इक्कीस लोगों की जान चली गई। उसके अगले ही दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसमें पांच लोगों के मरने की खबर आई। इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवस्थागत कमियों की कलाई खोल दी है। आमतौर पर किसी भी अस्पताल में मरीज इस उम्मीद में इलाज कराने जाते हैं, ताकि उनकी जिंदगी बच सके। मगर जब वहां अति सुरक्षित माने जाने वाले कक्ष में ही उनकी जान पर बन आए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अस्पतालों में सुरक्षा नियमों की जिस तरह अनदेखी हो रही है, उससे स्पष्ट है कि चिकित्सा एक ऐसे व्यवसाय का रूप ले चुकी है, जहां शायद जिंदगी की कोई कीमत नहीं। पिछले कुछ वर्षों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों में बार-बार गंभीर खामियां पाई गई हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मुजफ्फरपुर में हुए हादसे ने साफ कर दिया है कि अस्पताल में किस हद तक घोर लापरवाही बरती जा रही थी। मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का पांच सदस्यीय दल बनाया गया है। अब जांच की रिपोर्ट कब आएगी, उस पर क्या कार्रवाई होगी, यह आम लोगों को शायद ही पता चले। मगर इस घटना में मारे गए मरीज कभी घर नहीं लौटेंगे। बेहतर होता कि स्वास्थ्य विभाग संबंधित अस्पताल से तत्काल जवाब-तलब करता कि मरीजों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन निकास की व्यवस्था के साथ अभिरोधक उपाय उसने पहले क्यों नहीं किए। हेरत की बात है कि अस्पताल परिसरों में शॉर्ट सर्किट जैसी समस्या से निपटने को लेकर एहतरित बरतना और बुनियादी इंतजाम करना जरूरी नहीं समझा जाता है। जांच और राहत के आश्वासनों से इतर सवाल यह है कि इस तरह की व्यापक लापरवाही के लिए प्रशासन की अनदेखी की जवाबदेही कब तय की जाएगी! मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक बार फिर इस घटना ने राजधानी दिल्ली के लघु नागरिक प्रशासन और सुरक्षा इंतजामों की पोल एक बार फिर खोल दी है। दक्षिण दिल्ली के हौज रानी (मालवीय नगर) इलाके में स्थित 'प्लस रिस्टे वीरेंडो' (होटल में बुधवार, 3 जून 2026 की सुबह लगी इस भीषण आग ने 21 जिंदगियां निराल लीं। मरने वालों में 18 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं जो दिल्ली के बड़े अस्पतालों में इलाज कराने आए थे। इस हृदयविदारक हादसे ने पूरी राष्ट्रीय राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि अष्ट व्यवस्था, प्रशासनिक सुस्ती और नियमों को ताक पर रखकर इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करने का एक और खूनी सबूत है।

कहानी

निर्दयी जादूगर

एक व्यापारी की दाढ़ी बहुत लम्बी थी। सभी लोग उसे लम्बी दाढ़ी वाला बोलकर पुकारा करते थे। उसकी पत्नी कहीं थोड़ी गई थी और वह अपने पड़ोसी की बेटी सारा से विवाह करना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सारा के साथ हो भी गया।

विवाह के कुछ दिन बाद ही उस लंबी दाढ़ी वाले आदमी को किसी काम से दूसरे प्रदेश जाना पड़ा।

सने अपनी पत्नी से कहा। तुम इस घर की मालकीन हो इस घर की चाभी को अपने पास रखो। जब मैं ना रहू तो तुम अपनी सहेलियों को घर में बुला सकती हो, लेकिन छोटी चाबी से कोने वाला कमरा मत खोलना। उसमें जाना मना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कोठर सजा मिलेगी।

सारा अपने पति की इरावनी आंखें देख सहम गई। सारा ने वादा की वह उस कमरे को नहीं खोलेगी। जब उसका पती चला गया तो सारा ने अपनी सहेलियों को अपने घर बुला लिया। उन्हें अपने महंगे कपड़े और गहने दिखाए लगीं।

सभी सहेलियां सारा का महल जैसा घर देखा तभी एक सहेली ने सारा को कहा तुमने हमें अपने घर के सारे कमरे को दिखाया पर उस कोने वाले कमरे को बंद क्यों कर रखा है? वहां क्या है?

सारा ने बताया की उस कमरे को खोलने की इजाजत उसके पति ने उसे नहीं दी है। यह सुनकर दूसरी सहेली ने सारा से कहा कमाल कि बात है। तुम इस घर की मालकिन होने के बावजूद तुम्हें कमरे खोलने की इजाजत नहीं है?

अगली सुबह सारा अकेले में यह सोच रही थी। उसके पति ने कोने वाले कमरे में क्या छुपा रखा है। जिसे वह नहीं दिखा सकता है। सारा की इच्छा उस कमरे को देखने की ज्यादा बढ़ गयीं। उसने उस कमरे को खोलने का मन बना लिया। उसके बाद उसने चाबी ली और कोने वाले कमरे का गेट खोल दिया।

कमरे में कदम रखते ही सारा हैरान रह गई। वहां कांच का एक बड़ा सा मंड़क था। जिसमें बहुत से मेढ़क भरे हुए थे। उन मेढ़क में से एक मेढ़क ने उसे पुकारा और कहा, हम सभी लम्बी दाढ़ी वाले व्यापारी की पत्नियां हैं। हमने उसकी बात नहीं मानी तो सजा देते हुए उसने हमें मेढ़क बना दिया। वह एक दुष्ट जादूगर है। अब वह तुम्हें भी मेढ़क बना देगा।

सारा डर के मारे कांप उठी और अपने कमरे की ओर भागी। तभी सारा ने देखा कमरे की छोटी चाबी का रंग बदल गया है। उसने उस चाबी को पानी से धोकर देखा तब भी चाबी का पहले की तरह नहीं हुआ। क्योंकि वह एक जादुई चाभी थी।

अगली सुबह सारा का पति घर वापस आ गया और घर की चाबियां वापस मांगी। सारा ने उसे चाबियां का गुच्छा वापस कर दिया। उसने देखा छोटी चाभी का रंग बदल गया है। उसने बोला मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी।

अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरी पहले वाली सभी पत्नियों का हुआ था। तुम कितने निर्दयी इंसान हो तुम दुसरों को कितना कष्ट देते हो सारा ने गुस्से में कहा और घर से बाहर भाग गयीं।

जादूगर अपनी छड़ी धुमाते हुए सारा के पीछे उसे भी मेढ़क बनाने के लिए आगा। तभी सारा की आवाज सुन सभी पड़ोसी और सारा के परिवार वाले वहां पहुंच गए। सारा ने जादूगर की सारी बातें सब को बता दी। सभी लोगों ने पीट-पीटकर जादूगर को मार डाला।

सारा ने उस छड़ी को मदद से सभी मेढ़क बनी औरतों को भी आजाद कर दिया। उसके बाद उन्होंने जादूगर की सारी धन-दौलत को आपस में बांट ली और सभी आराम से रहने लगे।

इस कहानी से हमें यह सिखा मिलती है किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी कोई रिश्ता बनाने से पहले उसकी पुरी तहकीकात करनी चाहिए।



आशा जैन

वरिष्ठ पत्रकार

उक्त किस्सा बताता है कि यूरोप-अमेरिका में इंसान का जीवन कितना अनमोल है और सिर्फ एक जिंदगी बचाने के लिए कैसे एजेंसियां जमीन-आकाश एक कर देती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में मौत सिर्फ एक आंकड़ा है। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग से 21 लोगों की मौत ने एक बार फिर यह बात साबित की। प्रारंभिक जांच में फिर वही लापरवाहियां सामने आई हैं, जो लगभग हर अग्निकांड के बाद सामने आती हैं। उदाहरण के लिए होटल के पास सिर्फ छह कमरे बनाने की अनुमति थी, लेकिन 25 कमरे बनाए गए। होटल के पास अनिवार्य फायर एनओसी तक नहीं थी। इमारत में प्रवेश और निकास का सिर्फ एक दरवाजा था और कोई आपातकालीन द्वार नहीं था। इस हादसे में कई विदेशी भी मारे गए हैं।

विडंबना यह कि किसी हादसे से सीख नहीं ली जाती। बीते साल दिसंबर में गोवा नाइटक्लब में अग्निकांड हुआ, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। वह हादसा हाल के वर्षों का सबसे बड़ा 'सिस्टम फेलियर' केस माना जाता है। इस अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच में सामने आया था कि क्लब अवैध निर्माण पर चल रहा था, फायर एनओसी नहीं था, पर्याप्त आपातकालीन निकासी द्वार नहीं थे, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था और फायर अलार्म सिस्टम तक नहीं था। रिपोर्ट के ये निष्कर्ष इस तरह

सस्ती साबित की जाती नागरिकों की जान



सा ल 2009 की बात है। ब्रिटेन के आक्सफोर्ड में 16 साल के एक स्कूली छात्र ने आत्महत्या की कोशिश से कुछ मिनट पहले फेसबुक पर लिखा, 'मैं अब बहुत दूर जा रहा हूँ।' अमेरिका में वैठी उसकी फेसबुक मित्र ने इस संदेश को पढ़ा तो उसने तत्काल अपनी मां को बताया। मां ने आनन-फानन में मैरीलैंड पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने व्हाइट हाउस के स्पेशल एजेंट से संपर्क साधा और उसने फोरन वाशिगटन में ब्रिटिश दूतावास के अधिकारियों से। उन्होंने ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस से संपर्क किया और चंद मिनट बाद छात्र के घर का पता लगाकर पुलिस उसके घर जा पहुंची। जब तक वह घर के भीतर दौड़कर हुई, छात्र नौद की बहुत अधिक गोलियां खा चुका था। वह बेहोश पड़ा था। पुलिसकर्मियों ने कुछ ही पलों में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी जान बच गई। उक्त किस्सा बताता है कि यूरोप-अमेरिका में इंसान का जीवन कितना अनमोल है और सिर्फ एक जिंदगी बचाने के लिए कैसे एजेंसियां जमीन-आकाश एक कर देती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में मौत सिर्फ एक आंकड़ा है। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग से 21 लोगों की मौत ने एक बार फिर यह बात साबित की। प्रारंभिक जांच में फिर वही लापरवाहियां सामने आई हैं, जो लगभग हर अग्निकांड के बाद सामने आती हैं। उदाहरण के लिए होटल के पास सिर्फ छह कमरे बनाने की अनुमति थी, लेकिन 25 कमरे बनाए गए। होटल के पास अनिवार्य फायर एनओसी तक नहीं थी। इमारत में प्रवेश और निकास का सिर्फ एक दरवाजा था और कोई आपातकालीन द्वार नहीं था। इस हादसे में कई विदेशी भी मारे गए हैं। विडंबना यह कि किसी हादसे से सीख नहीं ली जाती।

बीते साल दिसंबर में गोवा नाइटक्लब में अग्निकांड हुआ, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। वह हादसा हाल के वर्षों का सबसे बड़ा 'सिस्टम फेलियर' केस माना जाता है। इस अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच में सामने आया था कि क्लब अवैध निर्माण पर चल रहा था, फायर एनओसी नहीं था, पर्याप्त आपातकालीन निकासी द्वार नहीं थे, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था और फायर अलार्म सिस्टम तक नहीं था। रिपोर्ट के ये निष्कर्ष इस तरह के लगभग हर अग्निकांड के बाद सामने आते हैं, जो साफ तौर पर नियामकीय विफलता दिखाते हैं। आग की घटनाओं के संदर्भ में तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत में लोग आग से कम, आग लगने से पहले की गई अनदेखी से ज्यादा मरते हैं। भारत में कई मामलों में मौत यहां कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था का एक नियमित परिणाम है। दिल्ली के जनकपुरी में एक युवक सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिर जाता है। घंटों तक मदद नहीं मिलती और उसकी मौत हो जाती है। नोएडा में एक इंजीनियर की कार खुले नाले में जा गिरती है। उसकी मौत के बाद सुरक्षा प्रबंधों तथा प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक इमारत के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में पानी भरने से तीन छात्र डूबकर मर जाते हैं। इस तरह के सड़कों उदाहरण हैं, लेकिन प्रशासनिक विफलता की कहानी वहीं रहती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2020 के बीच खुले गड्ढे और मैनेहोल में गिरकर 5,393 लोगों की मौत हुई। यानी औसतन हर दिन दो भारतीय ऐसी मौत मरते हैं, जो पूरी तरह रोकी जा सकती थीं। सवाल यह है कि गड्ढे खुले क्यों थे और

उन्के आसपास आवश्यक सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे? भारत में हर बड़े हादसे के बाद एक तयशुदा पटकथा चलती है। जांच के आदेश दिए जाते हैं। मुआवजे की घोषणा होती है। कुछ अधिकारियों का तबादला होता है। फिर अगला हादसा हो जाता है। दुखद यह है कि भारत में मौतें अक्सर किसी एक व्यक्ति की गलती से नहीं होतीं। वे कई संस्थाओं की संयुक्त विफलता से होती हैं। ठेकेदार लापरवाह होता है, विभाग आंखें मूंद लेता है, निरीक्षण औपचारिकता बन जाता है और राजनीतिक व्यवस्था केवल हादसे के बाद सक्रिय होती है। परिणामस्वरूप नागरिक मरता है और तंत्र इसीलिए प्रेस कांफ्रेंस करता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान केवल चुनाव नहीं होती। उसकी पहचान यह होती है कि वह अपने नागरिकों को कितनी सुरक्षा देता है। जिस देश में लोग गड्ढे, मैनेहोल, सीवरों, आग, भगदड़ और खराब सड़कों से मर रहे हों, वहां विकास के दावों की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है।

एक कड़वा सच यह भी है कि भारत में नागरिकों को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उस जगह से दूरी बनाए। इतना ही नहीं, कई जगह वे खुद भी कानून का उल्लंघन करने से नहीं हिचकते। मसलन, हमारे देश में हर साल लगभग 1.8 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। इनमें से करीब 30 हजार लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्होंने हेल्मेट नहीं पहना होता। देश की विशाल आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद संवेदनहीनता का कारण भी। बड़ी आबादी ने जान की कीमत को इतना कम कर दिया है कि न नागरिकों को ओर न सिस्टम को समझ आता है कि जीवन अनमोल है।

जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौती

देश में जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण एवं उससे होने वाले प्रभाव के अध्ययन हेतु भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी घुसपैठ एवं कुछ सामाजिक एवं धार्मिक समुदायों की जनसंख्या में असाधारण परिवर्तन के परीक्षण पश्चात प्रशासनिक एवं कानूनी ढांचे तथा नीतियों में परिवर्तन हेतु आवश्यक संसृति करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रकाश प्रभाकर नवलंकर की अध्यक्षता वाली कमेटी के गठन की घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ एवं अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी परिवर्तन से देश की शांति व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। गृह मंत्रालय की अधीसूचना के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में ऐसे जनसांख्यिकी परिवर्तन हुए हैं, जो सामान्य नहीं हैं। ये अवैध घुसपैठ, अनियमित आवागमन और प्रशासनिक ढिलाई के कारण हुए हैं। यह परिवर्तन विशेष तौर से सीमावर्ती इलाकों, औद्योगिक केंद्रों और सामाजिक तथा आर्थिक वृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, 'एक साजिश के तहत जनसंख्या को बदला जा रहा है। घुसपैठिये देश के युवाओं की रोजी-रोटी छिन रहे हैं, बहनों और बेटियों को निशाना बना रहे हैं, भोले भाले आदिवासियों को गुस्सा कर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।' प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर कार्रवाई हेतु ही उपरोक्त कमेटी का गठन किया गया है।

भारत में घुसपैठ की कहानी बड़ी लंबी है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो ऐसी आशा थी कि सांप्रदायिक सौहार्द होगा और बांग्लादेश सरकार आर्थिक क्षेत्र में ऐसे कदम उठाएगी कि किसी को अपना देश छोड़कर जीविकोपार्जन के लिए कहीं और न जाना पड़े, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आर्थिक कारणों से भारी संख्या में लोग में घुसपैठ करते रहे और अनुमान है कि इनमें से 70 प्रतिशत मुसलमान थे। हिंदू मुख्य रूप से वहां प्रताड़ित होने के कारण भारत पलायन कर रहे थे। बांग्लादेश चुनाव आयोग के अभिलेखों को देखने से कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। 1991 में बांग्लादेश में कुल 6,21,81,745 वोट थे, परंतु



इस सूची से 1995 में 61,65,567 लोगों के नाम काटने पड़े, क्योंकि उनका कहीं अता-पता नहीं था। 1996 में फिर 1,20,000 व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने पड़े, क्योंकि उनका भी कुछ पता नहीं चला। इतनी बड़ी संख्या में लोग हवा में नहीं गायब हो रहे थे। ये सब धीरे-धीरे भारत में घुसपैठ कर रहे थे। बांग्लादेश का बुद्धिजीवी वर्ग इस घुसपैठ का बरबाद समर्थन कर रहा था। असम के राज्यपाल रहते लॉफ्टिनैट जनरल एस्के सिन्हा ने आठ नवंबर, 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि असम में जिस तरह घुसपैठ हो रही है, उसे देखते हुए हो सकता है कि असम के सीमावर्ती मुस्लिम बहुल क्षेत्र को बांग्लादेश में मिला दिया जाए। बांग्लादेश में कुछ लोग 'ग्रेटर बांग्लादेश' की बात भी करने लगे थे। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने चार टास्क फोर्स का गठन किया था। उनमें से एक माधव गोडबोले के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2000 में प्रस्तुत की। उसमें स्पष्ट लिखा है कि

घुसपैठियों की संख्या एक करोड़ 50 लाख है। टास्क फोर्स के अनुसार तब प्रतिवर्ष करीब तीन लाख बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे थे। टास्क फोर्स ने सभी दलों को इस समस्या से निपटने में उदारता से बातें हुए लिखा कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक प्रगति के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में इस समस्या का संज्ञान लेते हुए इसे 'जनसांख्यिकी आक्रमण' कहा। इस तरह समय-समय पर चेतावनी मिलती रही, पर सरकारों के कान में जू नहीं रंगी और समय बीतने के साथ समस्या और गंभीर होती गई। आज शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जहां बांग्लादेशी कुछ न कुछ संख्या में न हों। बांगला और असम में तो इनकी बाढ़ है। 1951 में बांगला में मुस्लिम जनसंख्या 51,18,269 थी, 2011 में यह संख्या बढ़कर 2,46,54,825 हो गई। यानी 381.7 प्रतिशत की वृद्धि। असम में 1951 में मुस्लिम जनसंख्या 19,95,936 थी, 2011 में यह 5,28,34,345 हो गई। यानी 435.1 प्रतिशत की वृद्धि।

कर्नाटक में कलह



प्राथमिकता में है। यदि अन्य मंत्री भी ऐसी ही चाहत रखने लगे तो फिर डीके शिवकुमार के लिए

सरकार चलाना कठिन ही होगा। वैसे उनके सामने समस्या केवल रामलिंगा रेड्डी ने ही खड़ी नहीं की। एक अन्य मंत्री जमीर अहमद भी अपने मंत्रालय से नाखुश हैं। उनके समर्थक उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और मंत्री भी अपने विभागों से अस्तुत्त बर्बाद जा रहे हैं। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि किसी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया और कई मंत्री ऐसे हैं, जो बड़े नेताओं के सगे-संबंधी हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धमैया के बेटे भी शामिल हैं। कर्नाटक में नई सरकार बनने ही जो कुछ देखने को मिल रहा है, वह मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की समस्या बढ़ाने वाला ही नहीं, पार्टी में गुटबाजी को नए सिरे से उभारने वाला भी है। कर्नाटक का मामला कुछ-कुछ पंजाब की याद दिला रहा है। वहां भी कांग्रेस नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री

अमरिंद सिंह को हटाते ही गुटबाजी चरम पर पहुंच गई थी और फिर ऐसी स्थिति बनी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह फाजय का सामना करना पड़ा। फिलहाल कहना कठिन है कि कर्नाटक में क्या होगा, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में दो वर्ष शेष रह गए हैं, तब कलह के बीच नई सरकार के लिए ऐसा कुछ कर पाना कठिन होगा, जिससे कर्नाटक की समस्याओं का समाधान हो और कांग्रेस को मजबूती मिले। कर्नाटक का घटनाक्रम पार्टी नेतृत्व की भी मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि यह कांग्रेस शासित एक प्रमुख राज्य है और यह किसी से छिपा नहीं कि यहां भाजपा उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। यह शुभ संकेत नहीं है कि जब कर्नाटक की जनता को एक सक्षम सरकार चाहिए, तब डीके शिवकुमार सरकार की शुरुआत कलह से हो रही है।



ऐसे ड्रिवाइस का इस्तेमाल खतरनाक

इन दिनों तकनीक की मदद से हमारे कई काम आसान होते जा रहे हैं। लेकिन, कई बार तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो जाता है। एक नए अध्ययन के मुताबिक, ड्राइविंग के वक्त हैंड्स-फ्री ड्रिवाइस का इस्तेमाल भी काफी खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन पर बात करने के लिए कई लोग हैंड्स-फ्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, इस अध्ययन में कहा गया है कि हैंड्स-फ्री ड्रिवाइस के इस्तेमाल से भी ड्राइवर का ध्यान भंग हो सकता है। भारत में भी ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बातचीत करना गैरकानूनी है लेकिन, ज्यादातर लोग ड्राइविंग के दौरान हैंड्स-फ्री पर बात करते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना में कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में इस अध्ययन के सामने आने से इस मुद्दे पर और गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है।



ड्यूक 390 अगले साल तक

अस्ट्रेलिया की मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी केटीएम अपना ड्यूक 390 नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल अगले साल तक भारत में लॉन्च करेगी। हाल ही में इस ड्यूक की तस्वीरें यूरोप में टेस्टिंग के दौरान सामने आई हैं। केटीएम ड्यूक 390 के इस नए मॉडल में कई बदलाव नजर आ रहे हैं, साथ ही बाइक की स्टाइलिंग में काफी बदलाव किए गए हैं। बाइक के फ्यूल टैंक को बिल्कुल नया डिजाइन दिया गया है। इसके अलावा हेडलाइट क्लस्टर को भी बदला है। नए केटीएम ड्यूक 390 में ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, नया स्विचगैर और एलईडी इंडिकेटर लगाए गए हैं। बाइक में सिंगल सिटिलेअर इंजन लगा है, बताया जा रहा है कि इस बाइक के इंजन को भी पहले की तुलना में थोड़ा स्मूथ बनाया गया है ताकि ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो। इस नई ड्यूक 390 में पहले से बेहतर कूलिंग सिस्टम भी मौजूद है।



वीएमडब्ल्यू की स्टंट वाइक...

वीएमडब्ल्यू आगामी जी310आर बाइक भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के लिए उतार चुकी है। वीएमडब्ल्यू जी310आर के दो मॉडलों को चेन्नई-बेंगलुरु हाइवे पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया। आगामी मोटरसाइकिल वीएमडब्ल्यू की पहली बाइक है जिसको भारत में तैयार किया जा रहा है। इस बाइक को होसूर में टीवीएस मोटर्स के कारखाने में तैयार किया जाएगा। वीएमडब्ल्यू जी310आर को पहली बार 2016 ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। उम्मीद है कि इस बाइक भारतीय बाजार में अक्टूबर, 2016 तक लॉन्च किया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान एक दिलचस्प बात यह सामने आई कि बाइक बिना एंटी ब्रेक सिस्टम के दिखाई दी। दरअसल कंपनी किफायती दाम में बाइक लॉन्च करने की तैयारी में है। इसलिए भारतीय बाजार में इसके दो वैरिएंट लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा परीक्षक सवार के अनुसार, वीएमडब्ल्यू जी310आर की टॉप स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा है। वीएमडब्ल्यू जी310आर के माइलेज की बात करें तो यह 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। हालांकि यह आंकड़े अभी केवल अटकलें हैं। यह एक स्टंट बाइक है जिसको चार बार विश्व स्टंट बाइक चैंपियन रहे चुके क्रिस फीफर के सुझाव के साथ तैयार किया गया है। इस बाइक के ज़्यादातर फीचर्स स्टंट के ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।



ये नियम है फायदे के...

शास्त्रों के अनुसार निर्धारित नियमों का पालन करने से घर-परिवार को सुखी व समृद्ध बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करते रहने से घर में ऊपरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। सर्वप्रथम तुलसी को घर में स्थापित करें क्योंकि तुलसी साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपा हैं और भारत के हर भाग में सहज उपलब्ध हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं, वह घर सूना समझा जाता है। तुलसी का स्पृश कर घर में प्रवेश करने वाली वायु साक्षात् अमृत होती है। दैहिक स्वास्थ्य को सिद्ध करती है। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाने से न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है अपितु इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में धन-धान्य की वृद्धि करते हैं। घर में मंदिर की स्थापना करने से पूर्व ध्यान रखें की वहां सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आसानी से आ जा सके। ऐसा करने से ऊपरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जिस घर में एकाक्षी नारियल की पूजा होती है, वहां लक्ष्मी जी की कृपा होती है, अब व धन की कमी कमी नहीं आती। गोबर में लक्ष्मी का वास होने से इसे गोबर अर्थात् गौ का वरदान कहा जाना ज़्यादा उचित होगा। गोबर से लीपे जाने पर ही भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त होती है। गोबर से बने उपलों का यज्ञशाला और रसोई घर, दोनों जगह प्रयोग होता है। मान्यता है जिस जगह को प्रतिदिन गाय के गोबर से लीपा पोता जाता है वह जगह हमेशा पवित्र रहती है और उस स्थान में मां लक्ष्मी सर्वदा निवास करती हैं। ऐसे घर को धन-दौलत से समृद्ध करती हैं मां लक्ष्मी।

मलेशिया की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी ने भारत में रहने वाले हिंदुओं को डर्टी और अनवलीन बताया है। यूनिवर्सिटी के इस टीचिंग मॉड्यूल के ऑनलाइन पब्लिश होने के बाद इसे लेकर विवाद हो गया है। इसमें दावा किया गया है कि हिंदू लोग बॉडी पर गंदगी लगाने को निर्वाण प्राप्त करने का धार्मिक जरिया मानते हैं। सच तो यह है कि किसी भी धर्म का मर्म जाने बिना उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना, कोई निष्कर्ष निकालना सतही ज्ञान का प्रदर्शन करना है। यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने गंदगी कहकर हमारी भस्म की अवधारणा के बारे में अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है।



विकास का उपकरण

वास्तव में भस्म शिव या किसी और भगवान की दी हुई चीज नहीं है। यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। भारतीय संस्कृति में, उसे गहराई से किसी व्यक्ति के विकास के उपकरण के रूप में देखा गया है। सही तरीके से तैयार विभूति की एक अलग गुंज होती है। इसके पीछे के विज्ञान को पुनर्जीवित करने और उसका लाभ उठाने की जरूरत है। हमारे देश की संस्कृति में राख के बहुत से संदर्भ और अर्थ हैं राख एक वह जो जीवन का कट्टा सत्य है। प्राणत के बाद यह देह भी भस्मसात होगी ही। कई बार तीर्थ स्थानों में गुफाओं में धूनी रमाए तपस्या करते साधु देखे जा सकते हैं। हमारे लोकगीतों और शास्त्रीय संगीत में अनेक प्रसंगों में भस्म का जिक्र आया है जैसे भस्म अंग गौरी संग अधिक सुहाय है...। कवियों ने अपनी कविताओं में भी भस्म का खूब प्रयोग किया है श्रीचन्द्रकुवर बर्वाले ने 'ज्योति ओकरा' कविता में लिखा है "शोभित चंद्र कला मस्तक पर, भ्रम विभूति नम कलेवर कटि पर कृष्ण गजानिन सा घन गिरती घोर घोष कर पद पर दृज छटा सी दीप्त सुरुधि। तथा शिव पंचाक्षर स्तोत्र में लिखा है- नागन्द्रहाय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय विभूषिताय..।

राख से उपचार

अयुर्वेद में भी राख का विशेषकर पहाड़ी गाय के गोबर से बने उपले की राख का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। किसी बच्चे के पेट में दर्द होने पर गांवों में जब डाक्टर और दवा नहीं होती थी तो बुजुर्ग लोग दादी-नानी बच्चे के पेट में जलती अंगीठी से गर्म राख निकालकर मल देते और सेक करते थे तो आराम आता था। कई बार जब बच्चे की तठलीफ का पता नहीं चलता था और लगातार रोता था तो उसे गोद में लेकर रखने लोग मंत्र बोल-बोल कर राख का स्पर्श करते हुए कभी मां दुर्गा का, कभी हनुमान वालीसा का, कभी भगवान शंकर के, या अन्य देवी देवताओं का पाठ करते और बालक के माथे पर राख का तिलक लगाते और बच्चे दर्द मुक्त हो कर सो जाते। भारतीय संस्कृति में गो माता तो पूजनीय है ही तथा उसके रक्षायु गमंत्र और गोबर की सर्वोत्तम जैविक खाद तो है ही इसके अतिरिक्त गाय से प्राप्त दुध, दही, घी, मक्खन आदि पदार्थों का भी अयोग्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। गाय के गोबर के उपले की राख के भी अनेक प्रयोग हैं संक्रमण से जब कभी गज रोग हो जाता है और सर पर गीत कठोरे बन जाते व सिर के बाल उड़ जाते हैं तो उसके उपचार के लिए भी राख की आवश्यकता होती जो एक अलग विधि है। गाय के गोबर के उपले की राख में अत्यधिक औषधीय तत्व हैं। यों तो स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से संक्रमण रोगों पर काफी नियन्त्रण कर लिया गया है। फिर भी कभी-कभार कहीं न कहीं रोगों के दर्शन हो ही जाते हैं। बड़ी माता भयावह संक्रामक रोग है। जो शरीर पर निकले फफ़ालों के सूखने पर खुल्खुल से फैलता है उससे घेरा कुरुप हो जाता है कहीं बार-बार आंखों की रोशनी भी घटती जाती है जिस समय उसके फफ़ाले सूखने लगे तो उस समय उस स्थान पर कपड़े से छनी हुई गाय के गोबर के उपले की राख मलने से दम नहीं पड़ते। यह अनुभूत सत्य है।

सृष्टि का सार है भस्म...

मलेशिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत के हिंदू लोग बॉडी पर गंदगी लगाने को निर्वाण प्राप्त करने का धार्मिक जरिया मानते हैं। इस यूनिवर्सिटी की बात हिंदुओं द्वारा शरीर पर भस्म लगाने की ओर इशारा करती है। यूनिवर्सिटी के विद्वान भस्म को गंदगी और इसे शरीर पर लगाने को अवैज्ञानिक कथार दे रहे हैं। ये विद्वान न तो भस्म के विज्ञान को समझ पाए हैं, न भस्म के अध्यात्म को औ न ही भस्म के दर्शन को। दरअसल शिवपुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। इस सृष्टि के सार भस्म यानी राख को शिवजी सदैव धारण किए रहते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जानी है। शिवपुराण के लिए अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है, उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म शिवजी को अर्पित की जाती है। शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाया जाता है। भस्म की यह विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसे शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म धारण करने वाले भगवान शिव संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जहां जैसे हालात बनते हैं, हमें भी स्वयं को उसी के अनुरूप बना लेना चाहिए।



को निर्देशित और नियंत्रित करने की क्षमता है। इसके अलावा, शरीर पर उसे लगाने का एक सांकेतिक महत्व भी है। वह लगातार हमें जीवन के नश्वरता की याद दिलाती रहती है, मानो आप हर समय अपने शरीर पर नश्वरता ओढ़े हुए हों। 'भस्म' शब्द में 'भ' अर्थात् 'भर्त्सन्' अर्थात् 'नाश हो'। 'स्म' अर्थात् स्मरण। भस्म के कारण पापों का निर्मूलन होकर ईश्वर का स्मरण होता है। शरीर नाशवान है। इसे निरंतर स्मरण रखने का जो प्रतीक है, वह भस्म है; ऐसा भस्म शब्द का भावार्थ है। विभूति, रक्षा एवं राख ये भस्म के समानार्थी शब्द हैं। अपनी आहुति देकर मनुष्य का भस्म होना, अर्थात् अपनी इच्छा-आकांक्षा, दोष, अज्ञान एवं अहं का त्याग करना एवं मन की शुद्धता प्राप्त करना इसका मर्म है। मनुष्यदेह नश्वर है, इसलिए मरणोपरान्त उस देह को जलकर राख होना है। इसलिए कोई भी देहसक्ति न रखें। मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, यह भान रख मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए प्रत्येक क्षण को पवित्र तथा आनंदमय बनाने में प्रवृत्त रहें, यही भस्म सूचित करती है।

शरीर मूल पदार्थ नहीं

आम तौर पर योगी श्मशान भूमि से उठाई गई राख का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस भस्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अगला विकल्प गाय का गोबर होता है। इसमें कुछ दूसरे पदार्थ भी इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन मूल सामग्री गाय का गोबर होती है। अगर यह भस्म भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, तो चावल की भूसी से भस्म तैयार की जाती है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर मूल पदार्थ नहीं है, यह बस भूसी या बाहरी परत है। सुबह घर से निकलने से पहले, हम कुछ खास जगहों पर विभूति लगाते हैं ताकि हम अपने आस-पास मौजूद ईश्वरीय तत्व को ग्रहण कर सकें, शैतानी तत्व को नहीं। अगर भस्म को सही तरीके से तैयार किया

नश्वरता का आभास

भस्म यानी कुछ जलाने के बाद बची हुई राख। शिव जली हुई चिताओं के बाद बची हुई राख को भी अपने तन पर लगाते थे। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है, वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है। इसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के बाद बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। न उसके दुख, न सुख, न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण-अवगुण नहीं है, ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। विभूति, भस्म या पवित्र राख के इस्तेमाल के कई पहलू हैं। पहली बात, वह ऊर्जा को किसी को देने या किसी तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। इसमें 'ऊर्जा-शरीर'

किस दिशा में सिर रख कर सोएं... ?

पारंपरिक रूप से उत्तर दिशा में सिर रख कर सोने के लिए अक्सर हमें मना किया जाता है। क्या यह नियम पूरी दुनिया में सभी स्थानों पर लागू होता है? क्या है इसका विज्ञान? कौन सी दिशा सोने के लिए सबसे अच्छी है? किस दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए? यही जानने की कोशिश है यह आलेख।

आपने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सुना होगा। कई रूपों में अपनी चुंबकीयता के कारण पृथ्वी बनी है। इसलिए इस ग्रह पर चुंबकीय शक्तियां शक्तिशाली हैं। अगर हम उत्तर की ओर सिर करते हैं और 5 से 6 घंटों तक उस तरह रहते हैं, तो चुंबकीय खिंचाव हमारे दिमाग पर दबाव डालेगा। अगर कोई व्यक्ति एक हम से आगे निकल चुका है और उसकी रक्त शिराएं कमजोर हैं तो उसको रक्तस्राव और लकवे के साथ स्ट्रोक हो सकती है। शरीर यह बदलाव इसलिए लाता है

सुबह ऐसे उठें

अपनी दाहिनी तरफ घूमें: जब आप उठें, तो अपनी दाहिनी तरफ घूमें और फिर बिस्तर से बाहर आएं, क्योंकि नींद से उठते समय मेटाबोलिक प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। ऐसे में अचानक से बिस्तर छोड़ने पर दिल पर दबाव पड़ेगा।

अपने हाथों को मसलें: सुबह बिस्तर से उठने से पहले अपने हाथों को मसलें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। हथेलियों को मसलने से हाथों में स्थित सभी नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं और हमारा सिस्टम जल्दी से सजग हो जाता है।

मुस्कुराएं: सुबह उठ कर मुस्कुराएं! किसे देख कर? किसी को नहीं! क्योंकि आपका सुबह उठना अपने आप में एक बड़ी बात है। लाजों ऐसे लोग हैं जो कल रात सोए और आज सुबह नहीं उठे, लेकिन आप सुबह उठ गए। क्या यह बड़ी बात नहीं है? इसलिए मुस्कुराएं।

उठने के बाद यह करें

पारंपरिक रूप से यह भी कहा जाता है कि सुबह उठने से पहले हमें अपनी हथेलियां राइन्डनी करिए और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने पर हमें भगवान दिख सकते हैं। इसका संबंध भगवान के दिखने से नहीं है। हमारे हाथों में नाड़ियों का एक भारी जाल है। अगर हम अपनी हथेलियां राइन्डनी करें, तो सभी नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर तत्काल सजग हो जाता है। सुबह जाने पर भी अगर सुबह महसूस करते हैं, तो ऐसा करके देखिए, आपका पूरा शरीर तत्काल सजग हो जाएगा। तत्काल आपकी आंखों और आपकी हथेलियों के दूसरे पहलुओं से जुड़ी सारी नाड़ियां सजग हो जाती हैं। शरीर को हिलाने से पहले आपका शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय होने चाहिए। आपको सुस्त नहीं उठना चाहिए, इसका मकसद यही है।

खादी की लहर है...

केवीआईसी यानी खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग ने मंगलावर को कहा कि देश में खादी की लहर है और कई मंत्रालयों व संस्थानों ने दैनिक आधार पर हाथ से बुने परिधान का उपयोग शुरू किया है। खादी उत्पादों के लिए मांग बढ़ रही है और खादी दस्तकारों के लिए अधिक मानव ब्रम्ह सृजित कर रही है। जब 1920 के दशक में भारत में हाथ से बने खादी वस्त्रों की शुरुआत हुई तो यह केवल एक ढर्रा नहीं था, यह एक विचारधारा के रूप में सामने आया था। इसके सबसे बड़े प्रशंसक महात्मा गांधी थे और सृष्टी भारत की आत्मनिर्भरता, जितानी कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले कपड़ों से आजादी का प्रतीक बन गया था। आज भी यह कई नेताओं की पहली पसंद है। अब इसे लगातार फैशनेबल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय मौसम के लिए यह

सबसे दुरुस्त पहनावा है, जो पसीने और गर्मी से राहत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की यात्रा पर आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी खादी पहनने का सुझाव दिया था। फैशन डिजाइन कार्डीसल ऑफ इंडिया अनुसार यह बहुत ज़्यादा संभावना वाला बाजार है, खादी के कपड़े सस्ते हैं। भारतीय डिजाइनर जनता के साथ काम करना चाहते हैं, न कि कुछ खास लोगों के लिए। इस समय भारतीय कपड़ा बाजार में इसकी महज एक या दो फीसदी हिस्सेदारी है। यह अभी भी एक बचवाले कि खादी की छवि को बदलने की ये कोशिशें क्या वाकई कोई बदलाव ला सकेंगी। हालांकि, इसकी व्यापक लोकप्रियता में समय लग सकता है लेकिन खादी में बदलाव इससे जुड़े लाखों कारीगरों की जिंदगी को बदल सकता है।



जनगणना 2027 के प्रथम चरण की प्रगति एवं आंकड़ों की गुणवत्ता की समीक्षा बैठक आयोजित

वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत की जा रही हाउस लिस्टिंग की प्रगति एवं आंकड़ों की गुणवत्ता के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। प्रमुख जनगणना अधिकारी ने जनगणना कार्य के अंतर्गत हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया कि जिले में कुल 5306 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक निर्धारित हैं, जिनमें से 29६9 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जो कि कुल हाउस लिस्टिंग का 55.95 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि 14 जून से पूर्व हाउस लिस्टिंग के कार्य पूर्ण करने के निर्देश चार्ज जनगणना अधिकारी एवं तहसीलदारों को दिए हैं। उन्होंने इस दौरान जनगणना अधिकारी एवं तहसीलदार चौमू द्वारा 530 में से 530 तथा जालसू द्वारा 164 में से 164, चार्ज जनगणना अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी कालांडरा द्वारा 28 में से 28 शत-प्रतिशत हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का कार्य निर्धारित समायावधि से पूर्व पूर्ण करने पर ब्याडि देकर होसला अफजाही की। उन्होंने बताया कि चार्ज जनगणना अधिकारी एवं तहसीलदार तृंगा द्वारा 165 में से 163 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का कार्य पूर्ण कर 90 प्रतिशत से अधिक प्रगति हासिल की है। वहीं किशनगढ़-रेनवाल में 59 में से 55, कानोता में 20 में से 19 तथा शाहपुरा नगर परिषद क्षेत्र में 144 में से 138 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का कार्य पूर्ण कर 90 प्रतिशत से अधिक प्रगति दर्ज की गई है। प्रमुख जनगणना अधिकारी ने जिले के समस्त उपखण्ड जनगणना अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, चार्ज जनगणना अधिकारियों, तहसीलदारों, अधिशासी अधिकारियों, नगर परिषद आयुक्तों एवं चार्ज सहायकों को आंकड़ों की गुणवत्ता की सतत मॉनिटरिंग करने तथा जनगणना कार्य को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समायावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीईओ जिला परिषद प्रतिभा वर्मा, उपवन संरक्षक वी केतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय व जिला जनगणना अधिकारी देवयानी, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय मेघराज मीणा, संयुक्त निदेशक सांख्यिकी विभाग बानुलाल मीणा सहित संबंधित विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े थे।

प्राध्यापक, प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा-2025 के समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं संगीत विषय के पेपरों में क्रमशः 24.94, 33.53 एवं 27.44 प्रतिशत परीक्षार्थी रहे उपस्थित

वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक, प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा-2025 के अंतर्गत जयपुर जिले में विभिन्न विषयों की परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 06 जून को प्रातःकालीन पारी में आयोजित समाजशास्त्र विषय की परीक्षा के लिए कुल 6,597 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,645 परीक्षार्थी उपस्थित तथा 4,952 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार उक्त परीक्षा में 24.94 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि 06 जून को द्वितीय पारी में आयोजित अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा के लिए कुल 6,042 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2,026 परीक्षार्थी उपस्थित तथा 4,016 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार उक्त परीक्षा में 33.53 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं संगीत विषय की परीक्षा के लिए कुल 798 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 219 परीक्षार्थी उपस्थित तथा 579 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार उक्त परीक्षा में 27.44 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सम्पन्न हुईं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं।

पीएम स्वनिधि योजना के लंबित आवेदनों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित

वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शनिवार को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति, स्वीकृति एवं वितरण की प्रगति तथा विभिन्न कारणों से लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 27 जनवरी 2026 के बाद से योजना के अंतर्गत कुल 34,893 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 14,169 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 12,129 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। वहीं विभिन्न कारणों से लंबित 2,616 आवेदनों पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए तथा स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी एवं छोटे स्वरोजगार से जुड़े नागरिकों को सुलभ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी संबंधित विभाग एवं संस्थाएं समन्वय के साथ कार्य करें। उल्लेखनीय है कि पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ वर्ष 2020 में किया गया था। योजना का प्रथम चरण दिसंबर 2025 में पूर्ण हो चुका है तथा इसका क्रियान्वयन वर्ष 2030 तक जारी रहेगा। बैठक में शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न सरकारी एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राजस्थान के 4 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधी कार्यों की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत राजस्थान के चार शहरों- जयपुर, उदयपुर, अलवर एवं नाथद्वारा-द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 की तैयारियों एवं स्वच्छता क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों की स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुखी एवं जनसहभागिता आधारित बनाए के निर्देश दिए। सभीवालों में आयोजित समीक्षा बैठक में चारों शहरों द्वारा स्वच्छता प्रबंधन, कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण, जनजागरूकता तथा नवाचार आधारित पहलों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक पहल का डेटा आधारित विश्लेषण किया जाए तथा प्रस्तुतिकरण में कार्यों से प्राप्त परिणाम, लाभार्थियों की संख्या, शामिल मानव संसाधन और संरचित लाभ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं। उन्होंने उपलब्धियों को प्रभावी इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत करने पर भी बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि वेस्ट-टू-वेल्थ एंव नवाचारों को अन्य शहरों में भी अपनाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था, स्पष्ट रूप से निर्धारित कलेक्टरन रुट्स, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा शहरों में दृश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रयास नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने चाहिए तथा कचरा संवेदनशील स्थलों को समाप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वच्छता व्यवस्था में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए स्वचालित ढंड प्रणाली जैसे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने पर्यटन स्थलों एवं प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों में यांत्रिक सफाई को बढ़ावा देने तथा जनजागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में नाथद्वारा जिले द्वारा विकसित वेस्ट-टू-वेल्थ मॉडल, कचरा मुक्त क्षेत्रों के विकास तथा जनजागरूकता आधारित पहलों की मुख्य सचिव ने सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार अन्य नगर निकायों के लिए भी प्रेरणादायक हैं

पशुपालकों को दी गोपाल क्रेडिट कार्ड एवं मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सुविधा- सीएम भजनलाल शर्मा

वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए डबल इंजन सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। इसी क्रम में सबसे पहले पानी-बिजली की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को भीलवाड़ा के खारी कालम्बा ग्राम पंचायत में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस ग्राम पंचायत में नवीन कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने एवं नवीन कृषि पर्यवेक्षक पद के सृजन की घोषणा की। साथ ही, विद्यार्थियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए जल उपलब्धता



का रोडमैप बनाया। इसके तहत दशकों से अटकी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया। इसी क्रम में रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, आईजीएनपी एवं गंगनहर के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ माही, देवास तथा सोम-कमला-अंबा, ब्राह्मणी नदी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि

कैबिनेट मंत्री कुमावत ने बिजली-पानी के लिए अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश



वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री व पाली विधायक जोरानाम कुमावत ने शनिवार को पाली के सुमेरपुर में नगरपालिका सभाकक्ष में विभिन्न प्रशासनिक विभागों के आला अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्र की बिजली और पेयजल समस्याओं पर चर्चा की गई, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान क्षेत्र में हो रही बिजली कटौतों को लेकर उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारियों को आवश्यक उन्होंने विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए ढीले तार कसने, पड़ों की कटाई-छटाई करवाने तथा आरडीएसएस स्कीम के तहत नए ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। कुमावत ने कहा कि पिछले दिनों आए तृष्णन के कारण बड़ी संख्या में बिजली के खम्भे टूट जाने से आपूर्ति बाधित हो गई थी। जल्द ही शेष कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के

बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में भूमि आवंटन संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश - मुख्य सचिव

वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है तथा भूमि आवंटन से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में भूमि उपलब्धता अथवा अन्य कारणों से बाधाएं आ रही हैं, वहां वैकल्पिक भूमि की संभावनाओं का परीक्षण कर त्वरित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं ताकि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में अनावश्यक विन्म्व न हो। शनिवार को सचिवालय में आयोजित राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की बैठक में मुख्य सचिव ने भूमि आवंटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागावार लंबित प्रकरणों की स्थिति का विस्तृत अवलोकन करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का निराकरण करें तथा प्रत्येक प्रकरण की निष्पत्ति मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि कई मामलों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने अथवा उपयुक्त भूमि चिन्हित नहीं होने के कारण प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे मामलों में

व्यवहारिक एवं विधिसम्मत विकल्पों पर कार्य करते हुए समाधान तलाश जाएं। उन्होंने जिला स्तर पर भी लंबित प्रकरणों की सतत समीक्षा करने तथा आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2024-25, 2025-26 तथा 2026-27 की बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में मामलों में भूमि आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में आवश्यक प्रक्रियाएं प्रगतिरत हैं। विभागावार एवं जिलावार लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। बैठक में राजस्व,उपनिवेशन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही, समस्त जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में मौजूद रहे।

विभिन्न विभागों की लंबित एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों की प्रगति की समीक्षा

वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 में घोषित भर्ती कैलेंडर की प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार युवाओं को अधिक्राधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने तथा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने विभागों को भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित प्रशासनिक, वित्तीय, नियम संशोधन तथा अन्य आवश्यक कार्यालयियों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, संबंधित विभागों तथा भर्ती एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखा जाए ताकि भर्ती प्रक्रियाओं में अनावश्यक विन्ध नहीं हों। गृह विभाग की उप निरीक्षण को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा



कि विभिन्न विभाग भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। गृह विभाग की उप निरीक्षण को एवं कॉन्स्टेबल भर्ती, प्रशासनिक सुधार विभाग

की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, स्वायत्त शासन विभाग की सफाई कर्मचारी भर्ती, पंचायतीराज विभाग की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सपोर्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को 6 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि दी। वहीं, राज्य सरकार भी 3 हजार रुपये की सम्मान निधि दे रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक एवं जैविक खेती के जरिए अच्छी पैदावार से किसान अपनी आय को बढ़ाएं। स्थानीय कृषि उपज के अनुसार प्रोसेसिंग इकाइयों की क्षमता एवं दूध संकलन केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर की अनुदान दिया जा रहा है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से पशुपालकों को आर्थिक संबल मिला है। हमारी सरकार ने पशुओं के इलाज के लिए विशेष भर्ती को विकसित करने, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने तथा भारतवर्ष में 2070 तक कार्बन टटस्थता तक पहुंचाने में राजस्थान प्रदेश की अग्रिम भूमिका को देखते हुए राजस्थान को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में मिशन 'हरियालो राजस्थान' को महता को देखते हुए इसके व्यापक क्रियान्वयन हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले को 66 लाख 82 हजार 538 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है जिसमें से 45.64 लाख पौध जिले की विभिन्न नर्सरियों में तैयार की गई हैं। शेष पौधों की व्यवस्था निजी स्तर पर की जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि पौधारोपण कार्य हेतु संबंधित विभागों द्वारा लक्ष्यानुसार गढ़े खोदने के कार्य किया जा चुका है।उन्होंने बताया कि पौधारोपण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल एप

जयपुर में मिशन हरियालो राजस्थान को गति: 66 लाख पौधारोपण का लक्ष्य, जियोटैगिंग से होगी पूर्ण पारदर्शिता



वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

मिशन हरियालो राजस्थान की जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं राज-उन्मत्ति की 6वीं बैठक में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा जिला कलक्टर संदेश नायक ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में की। जिला कलक्टर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने, राजस्थान में कृषि वालिकी को विकसित करने, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने तथा भारतवर्ष में 2070 तक कार्बन टटस्थता तक पहुंचाने में राजस्थान प्रदेश की अग्रिम भूमिका को देखते हुए राजस्थान को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में मिशन 'हरियालो राजस्थान' को महता को देखते हुए इसके व्यापक क्रियान्वयन हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले को 66 लाख 82 हजार 538 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है जिसमें से 45.64 लाख पौध जिले की विभिन्न नर्सरियों में तैयार की गई हैं। शेष पौधों की व्यवस्था निजी स्तर पर की जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि पौधारोपण कार्य हेतु संबंधित विभागों द्वारा लक्ष्यानुसार गढ़े खोदने के कार्य किया जा चुका है।उन्होंने बताया कि पौधारोपण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल एप

जोधपुर में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने ली अपराध समीक्षा बैठक; अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के लिए निर्देश

वाँइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

हानिदशक पुलिस राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने शनिवार को जोधपुर रेंज कार्यालय में रेंज स्तरीय अपराध समीक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस सत्येन्द्र सिंह सहित जोधपुर ग्रामीणी, फत्तोदी, बालोता, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिराही और जालौर जिलों के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। बैठक में रेंज की भौगोलिक स्थिति और वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य पर व्यापक चर्चा की गई। महानिदेशक पुलिस शर्मा ने रेंज में हुए हालिया अपराधों की गहन समीक्षा की और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संगठित अपराधियों के विरुद्ध अधिक से अधिक सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से ड्रग माफिया और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने, उनके मुखियाओं के विरुद्ध प्रभावी विधििक कार्यवाही करने तथा तस्करी की काली कमाई से अर्जित उनकी संपत्तियों को जब्त करवाने जैसी कठोर कार्यवाही अमल में लाने के लिए जिला कक्षाओं को पाबंद किया। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष मंथन हुआ। डीजीपी ने महिला सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं, बालकों एवं कमजोर वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने और पुलिस मुख्यालय स्तर से वर्तमान में

प्रक्रियाधीन हैं और सवा लाख पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पोपरलीक पर लगाम लगाई है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया। इसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए। जिनमें से अब तक 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा नीति भी जारी की है। योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है। किसान हरफूल ने बताया कि मैंने पॉलीहाउस, सोलर एवं फव्वारा योजना का लाभ लिया है। इन योजनाओं के माध्यम से आधुनिक खेती करना आसान हुआ है, विशेषकर पॉलीहाउस के जरिए खीरे की खेती से मेरी अच्छी आय हुई है। किसान पुरुषोत्तम ने कहा कि उद्यानिकी विभाग से योजनाओं की जानकारी लेकर आंवला और नींबू की बागवानी से मेरी अच्छी आय हो रही है। आंवला की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी भी कर रहा हूं। फिलहाल मेरी 30 से 35 लाख रुपये की आय हो रही है।

के माध्यम से जियोटैगिंग की जायेगी। उन्होंने बताया कि साथ ही गत वर्ष में किए गए पौधारोपण की रि-जियो टैगिंग कर जीवितता भी अपडेट की जाएगी। जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान जैसे मरुदेश जहाँ आँकटाल से पानी की कमी रही है वहाँ जल संरक्षण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान भूजल विभाग द्वारा 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान का संचालन वर्षाजल की एक-एक बूँद का संरक्षण, संवर्धन व जल पुनर्भरण संरचनाओं का जनसहभागिता से निर्माण कर राज्य में गिरते भूजल स्तर को रोकने के साथ -साथ आमजन को जागरूक कर व्यवहार परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 125 संरचनाओं के लक्ष्य के विरुद्ध 254 रिचार्ज स्ट्रक्चरों का निर्माण किया जा चुका है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 125 संरचनाओं के विरुद्ध 741 रिचार्ज स्ट्रक्चरों का निर्माण आज दिनांक तक किया जा चुका है। जिला कलक्टर ने रीको सॉल्ट सभी विभागों को अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन हेतु संरचनाओं का निर्माण करने हेतु निर्देशित किया है। इस दौरान जिला कलक्टर ने सीएमओ, जनसुनवाई व संपर्क पोर्टल पर दर्ज जिले से संबंधित सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से पूर्ण संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश



चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों का क्रियान्वयन सजगता से करने पर विशेष बल दिया। जोधपुर रेंज के कई जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटी होने के कारण महानिदेशक ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरी सतर्कता बरतते हुए सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। इन क्षेत्रों में कर्मजुनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देकर अपराधियों, अवैध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। बैठक के समापन पर डीजीपी शर्मा ने सभी अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि देश में लागू हुए नवीन आपराधिक कानूनों में पुलिस को कई विशेष और प्रभावी प्रावधान दिए गए हैं। अधिकारी इन नए कानूनी प्रावधानों का कड़ाई और बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें, ताकि राजस्थान पुलिस का मूल ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय धरातल पर पूरी तरह सार्थक हो सके।

हेतु परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा। भर्ती अन्य पदों पर भर्ती तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विरुद्ध अब 6000 पदों पर भर्ती को कार्यावाही सम्पादित की जायेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी ने बताया कि अगवत कराया कि 53 हजार 749 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया संचालित है जिसमें दिव्यांग श्रेणी, खेल प्रमाण पत्रों एवं चिकित्सा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी। अन्य प्रमाणित अधिकारी के रिक्त पदों की अर्धना शीघ्र संबंधित भर्ती एजेंसी को प्रेषित कर दी जायेगी। 2 हजार नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर भर्ती नियमों में संशोधन के परचात समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर ली जायेगी। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पदों को विभाग में प्राल रही पूर्व से प्रक्रियाधीन भर्तियों में विभाग से प्राप्त अतिरिक्त रिक्त पदों को शामिल कर भर्ती की कार्यवाही कर रही है।

रिपोर्ट में दावा: तिब्बत पर चीन की पकड़ और मजबूत, मानवाधिकार हनन बढ़ने का दावा; तिब्बती भाषा और धर्म पर संकट



वाँडस ऑफ प्रतिज्ञा धर्मशाला

तिब्बती मानवाधिकार और लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) ने दो नई रिपोर्ट जारी करके बताया कि 2025 में तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति और भी गंभीर हो गई, क्योंकि चीन ने यहां अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया है। चीनी अधिकारियों ने इस क्षेत्र पर राजनीतिक और वैचारिक नियंत्रण मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। टीसीएचआरडी की बृहस्पतिवार को तिब्बत में मानवाधिकार स्थिति पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2025 और धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट (2012-2025) जारी की। इसमें में कहा गया है, चीन की नीतियां तिब्बती सांस्कृतिक, धार्मिक और नागरिक स्वतंत्रता के लिए लगातार खतरा बन रही हैं। बीते वर्ष यहां पर दमनकारी गतिविधियां और बढ़ीं जिसमें मंदिरों की क्षति, तिब्बती भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली नीतियां भी शामिल हैं। टीसीएचआरडी की कार्यकारी निदेशक तेनजिन दावा ने बताया कि चीन की ओर से हाल में लागू किए गए शिक्षा कानून के तहत प्रारंभिक शिक्षा में पुस्तकें हटाई (चीन की मानक मंदिरों भाषा) का उपयोग बढ़ा, जिससे तिब्बती भाषा की शिक्षा और भी हाशिए पर चली गई है। आलोचकों का कहना है यह नीति व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो तिब्बती संस्कृति और विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में बाधक है। रिपोर्ट में शांतिपूर्ण सभाओं पर बढ़ते प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया गया है। खनन परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकास के विरोध में प्रदर्शन कर रहे तिब्बतियों को कथित तौर पर गिरफ्तारी, धमकी, निगरानी और अन्य दंडात्मक उपायों का सामना करना पड़ा है। बताया जाता है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाने वाली परियोजनाओं का विरोध करने वाले पूरे समुदायों को सामूहिक दंड का सामना करना पड़ा है। टीसीएचआरडी ने रिपोर्ट में चिंता जताई है कि विदेशों में रहने वाले तिब्बती कार्यकर्ताओं और धार्मिक हस्तियों के खिलाफ दमन चक्र जारी है। रिपोर्ट में तिब्बती धार्मिक नेता तुलुक हुंगकर दोरजे की कथित तौर पर न्यायेतर हत्या का जिक्र किया है जिन्हें विगतनाम में एक अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट तिब्बती बौद्ध धर्म पर राज्य के बढ़ते नियंत्रण का और अधिक विस्तार से वर्णन करती है। इसके मुताबिक, तिब्बती बौद्ध मठों को नियंत्रित करने वाले संशोधित नियम जनवरी 2025 से लागू हुए जिसके तहत धार्मिक संस्थानों और भिक्षुओं को चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व का समर्थन करने पर बाध्य किया जाता है।

सुनामी में बदला तृणमूल का संकट: अब संसदीय दल में टूट तय, ममता की बैठक से सांसद-विधायकों की दूरी; उठे कई सवाल

वाँडस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

चुनावी हार के बाद विधायक दल में टूट के बाद अब तृणमूल के संसदीय दल में टूट तय है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी चौतरफा संकट में हैं। शुक्रवार को उनकी ओर से बुलाई गई सांसदों-विधायकों की बैठक में तृणमूल के अस्तित्व को लेकर यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया। बैठक में पार्टी के 41 सांसदों में से महज छह पहुंचे। इतना ही नहीं, हालिया घटनाक्रम में विधायकों के विरोधी गुट से दूर रहने वाले 21 में से महज 8 विधायकों की हाजिरी लगी। अहम तथ्य यह है कि बैठक में पहुंचने वाले मुस्लिम विधायकों में फिरहाद हकीम के रूप में इकलौते विधायक और संसदीय दल में सभी छह मुस्लिम सांसदों की अनुपस्थिति संकट का इशारा है। गौरतलब है कि क्रतव्रता बनर्जी के अनुवाय में जब विधायक दल में फूट पड़ी तो इसमें टीएमसी के जोते 31 मुस्लिम विधायकों में 17 विधायक शामिल थे। शुक्रवार को बैठक में बाकी बचे 14 मुस्लिम विधायकों में उपस्थित इकलौते फिरहाद हकीम बृहस्पतिवार को ही कोलकाता में मरण पद से इस्तीफा दे चुके हैं। चुनावी हार के बाद तृणमूल में जारी उथल पुथल दरअसल पार्टी नेताओं में अविश्वास के लिए उपजा हुआ भय है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि तृणमूल से दूरी बनाने वाले सभी नेताओं की इच्छा पार्टी में शामिल होने की है। यह अविश्वास के संकट के साथ भाविष्य में जांच का सामना करने की बन रही स्थिति से उपजा भय है। इनमें से ज्यादातर नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं। इसलिए पार्टी नेतृत्व तत्काल निर्णय करने से बच रहा है। विधानसभा चुनाव प्रचार में पार्टी का चेहरा बनी सायानी घोष, मोहुआ मोड़ना ने भी बैठक से दूरी बनाई। संकेत साफ है कि संसदीय दल का बड़ा हिस्सा भी विधायक दल की तरह विरोधी गुट से हाथ मिला लेगा। बैठक में सांसदों में अभिषेक बनर्जी, करणिका बनर्जी, माला रॉय, सुदीपा बंदोपाध्याय, डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेना ही शामिल हुए। टीएमसी में मंचो उथल पुथल और मंत्रियों के विभागों में बंटवारे के बाद राज्य के सीएम शुभेंद्र अधिकारी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर उन्होंने भावी रणनीति पर चर्चा की। दरअसल टीएमसी में टूट को ले कर भाजपा असमंजस में हैं। रणनीति यह है कि विरोधी गुट एनसीपी, शिवसेना की तरह पार्टी पर अधिकार जमाए। दरअसल पार्टी के एक धड़े को लगता है कि भाजपा में विलय या टीएमसी के अस्तित्व खत्म होने पर राज्य में वाम मोर्चा का उभार होगा जो अविश्वास में पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। ममता ने अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव पद पर बरकरार रखा है। पूर्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। डोला सेन और डेरेक ओब्रायन को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव बनाया है।

नीट पेपर लीक: शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रुकती धांधली; तंत्र में बदलाव बेहद जरूरी

वाँडस ऑफ प्रतिज्ञा पुणे

देश में नीट परीक्षा को लेकर मचा बवाल धमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने इस संकट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पुणे में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान पवार ने कहा कि मेंडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) के संचालन में यदि तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का सही समय पर इस्तेमाल किया गया होता, तो आज यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। शरद पवार ने कहा कि इस पूरे घोटाले को तकनीक की मदद से रोका जा सकता था। जब उनसे पूछा गया कि क्या एआई के उपयोग से नीट घोटाला टल सकता था, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर यह काम पहले ही कर लिया गया होता, तो आज देश के सामने यह नौबत ही नहीं आती। पवार ने एआई को लेकर कहा कि आज कुछ से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, हर क्षेत्र में इसके ज़रिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। हमें हर क्षेत्र में एआई को अपनाने के प्रयास तेज करने चाहिए। एनटीए के मौजूदा घटनाक्रम पर बात करते हुए शरद पवार ने किसी का नाम लिए बिना एक वरिष्ठ अधिकारी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी गई है, वह अतीत में उनके साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले दो महीनों के भीतर उनके काम के परिणाम सबके सामने दिखने लगेगे। बता दें कि तीन मई को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दिया गया था। इस मामले की जांच फिफ्टहल सीबीआई कर रही है, जिसने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।

चार्जशीट के दस्तावेजों तक आरोपी की पहुंच रोकी नहीं जा सकती', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

वाँडस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी आरोपी को चार्जशीट का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे दस्तावेजों को छिपाना आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह फैसला जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एस चंद्रकर की पीठ ने सुनाया। पीठ ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल वीके सिंह को कुछ अत्यधिक गोपनीय दस्तावेजों की टाइट की हुई प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मेजर जनरल वीके सिंह 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत 2007 में दर्ज एक मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं। पीठ ने गौर किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह नहीं कहा है कि सिंह द्वारा मांगे गए दस्तावेज मुकदमे के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। अभियोजन पक्ष को एकमात्र आपत्ति यह थी



कि ये दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से अत्यधिक गोपनीय हैं। इसके साथ ही अगर इनकी प्रतियां दी गईं, तो उनके सार्वजनिक डोमेन में आने की संभावना है। अदालत ने कहा, 'यह एक सुस्थापित कानून है कि किसी भी आरोपी को चार्जशीट का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों, जिनमें सामान्य डायरी के रिकॉर्ड भी शामिल हैं, तक पहुंच से नहीं रोका जा सकता है। अगर ऐसे दस्तावेज सद्भावना से प्राप्त किए गए हों, अभियोजन के मामले के लिए प्रासंगिक हों, और लोक अभियोजक द्वारा न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के हित में उनका खुलासा

आवश्यक माना गया हो।' पीठ ने आगे कहा, 'ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे दस्तावेजों को छिपाने से आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।' शीर्ष अदालत ने यह आदेश सिंह को उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने पिछले साल सितंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के दिसंबर 2009 के आदेश को संशोधित किया था, जिसमें अभियोजन पक्ष को सिंह द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। सिंह ने ट्रायल कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के तहत एक आवेदन दायर कर अभियोजन पक्ष को कुछ ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी, जो चार्जशीट का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें नहीं दिए गए थे। सीआरपीसी की धारा 207 आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने से संबंधित है। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष

अदालत ने कहा, 'हमारी राय में, चार्जशीट का हिस्सा होने और उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के कारण, उक्त दस्तावेजों को वादी (सिंह) को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।' पीठ ने यह भी कहा कि आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के हितों को संतुलित करने के लिए, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के साथ, उन्होंने सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारी से एक न्यायसंगत प्रस्ताव के साथ आने को कहा था। सुनवाई के दौरान विधि अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि वे उन दस्तावेजों की एक टाइट की हुई प्रति देंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि सिंह उनका इस्तेमाल केवल अदालत की कार्यवाही के उद्देश्य से कर सकते हैं। दस्तावेजों को किसी भी तरह से प्रसारित नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की जीडीपी वृद्धि को मजबूती का प्रतीक बताया, मोदी के नेतृत्व को सराहा

वाँडस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी के 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आर्थिक प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह भारत की मजबूती और उस टोस आधार को दिखाता है, जिसे पिछले 12 वर्षों में 'रिफॉर्म, प्रॉस्पेक्ट' के नाम के जरिए तैयार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, 'ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी और चौथी तिमाही में यह रफ्तार बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई। यह भारत की मजबूती और उस टोस आधार को दिखाता है, जिसे पिछले 12 वर्षों में 'रिफॉर्म, प्रॉस्पेक्ट' के मंत्र के जरिए तैयार किया गया है।' इस दौरान, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने आरोप पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास के साथ-साथ स्थिरता, आत्मनिर्भरता, टिकाऊपन और विश्वसनीयता को भी आगे बढ़ाया है। राष्ट्र-निर्माण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, इनवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमिता पर उनका ध्यान और अभूतपूर्व वैश्विक



चुनौतियों के बीच देश को सही दिशा देने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मनिर्भर, मजबूत और दुनिया भर में सम्मान पाने वाली आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।' राजनाथ सिंह ने आगे लिखा, 'जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत' के विजन को आगे बढ़ रहा है। विकास की यह शानदार कहानी नए अवसर पैदा कर रही है। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को मजबूत कर रही है। इससे पहले, केंद्रीय गृह अमित शाह ने जीडीपी के 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने पर प्रसन्नता जताई। अमित शाह ने शुक्रवार को 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

की ओर से शुरू किए गए दूरदर्शी आर्थिक सुधार देश में आर्थिक समृद्धि को निरंतर गति दे रहे हैं, जिससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ऐसे समय में जब विश्व आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, भारत की 7.7 प्रतिशत की विकास दर और सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए उनका प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि पिछले 12 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था ने कितनी मजबूती हासिल की है। चाहे महामारी का दौर हो या युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियां, मोदी जी की दूरदर्शी नीतियां ही देश को हर संकट से सुरक्षित रूप से पार ले जा रही हैं।'

राज्यसभा चुनाव: विपक्ष में असंतोष से भाजपा की झारखंड और मप्र में जगी उम्मीद, नटराजन को लेकर नाराजगी

वाँडस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

राज्यसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में कांग्रेस और झारखंड में झामुमो-कांग्रेस के बीच जारी खींचतान में भाजपा को अपने लिए नई उम्मीद नजर आ रही है। मध्यप्रदेश में जहां कांग्रेस में बाहरी मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाने से असंतोष है, वहीं सहमति के बिना कांग्रेस के झारखंड में उम्मीदवार घोषित करने से झामुमो नाराज है। इस स्थिति से खुश भाजपा जरूरी संख्याबल की कमी के बावजूद झारखंड में एक और मप्र में तीसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। दरअसल मध्यप्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय की ना के बाद दूसरे पूर्व सीएम कलमनाथ को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी। हालांकि बृहस्पतिवार को जारी सूची में पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की करीबी और तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन का नाम था। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में असंतोष है और यह असंतोष पिछले चुनाव की तरह ही क्रॉस वॉटिंग का कारण बन सकता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, कलमनाथ को राज्यसभा टिकट नहीं मिलने से छिद्रवाड़ा क्षेत्र के पांच कांग्रेस विधायकों को झटका लगा है। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी पूर्व सीएम को उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में उन इन विधायकों का रुख क्या रहता है, इस पर सभी की नजरें हैं। हालांकि असंतोष की भ्रमक के बाद सतर्क कांग्रेस नेतृत्व ने शनिवार को विधायकों की



बैठक बुलाई है। बिहार, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में क्रॉस वॉटिंग का नुकसान झेल चुकी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि हाल ही में हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि क्रॉस वॉटिंग की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी। राज्य में दो सीटों पर

चुनाव है। यहां एक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 28 मतों की जरूरत है। विपक्षी गठबंधन के पास दो सीट जीतने के लिए ठीक 56 मत हैं। जबकि भाजपा के पास 24 मत हैं। यहां झामुमो बिना चर्चा के कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने से नाराज है। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें एक सुर में दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मांग की गई। चूंकि कांग्रेस के पास महज 16 विधायक हैं, ऐसे में उसे 12 मत हासिल करने के लिए सहयोगियों का समर्थन चाहिए।

छह घंटे में सिलीगुड़ी से दिल्ली, पश्चिम बंगाल को मिलेगी बुलेट ट्रेन की सौगात- रेल मंत्री

वाँडस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को राज्य के लिए कई बड़े रेल परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली-वाराणसी-पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही है। इसके पूरा होने के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा करीब छह घंटे में संभव हो सकेगी। रेल मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास को रेल गति दी जा रही है। उनके अनुसार राज्य में 102 नए अमृत भारत स्टेशनों का विकास किया जाएगा, जिनमें से 10 स्टेशनों का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि बंगाल में पहले से नौ बड़े भारत एक्सप्रेस और 13 अमृत भारत ट्रेनों संचालित हो रही हैं तथा वंदे भारत स्लीपर सेवा की शुरुआत भी सबसे पहले इसी राज्य से हुई थी। कोलकाता मेट्रो के विस्तार का उल्लेख करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शहर के लिए 60 नई नेक्स्ट जेनरेशन मेट्रो ट्रेनों लाई जाएंगी। इसके अलावा डानकुनी से सूरत तक पूर्व-पश्चिम फ्रेट कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिससे माल परिवहन को नई गति मिलेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। रेल मंत्री ने राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए बड़े केंद्रीय आवंटन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रतिशोध गठबंधन (यूपीए) सरकार के समय पश्चिम बंगाल को रेलवे के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये मिलते थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह राशि बढ़कर 14,205 करोड़ रुपये हो गई है। उनके अनुसार अब अनारपित प्रमाणपत्र (एनओसी) और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने लगा है, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर रेलवे परियोजनाओं में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार के कारण कई विकास कार्य बाधित रहे, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने से केंद्र और राज्य मिलकर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकेगा।

विधानपरिषद चुनावों से पहले सुप्रिया सुले का बड़ा ऐलान, खरीद-फरोख्त पर रोक के लिए लाएंगी विधेयक

वाँडस ऑफ प्रतिज्ञा पुणे

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि वह संसद में एक विधेयक पेश करेंगी, जिसमें उन चुनावों में अधिक पारदर्शिता लाने की मांग की जाएगी, जहां खरीद-फरोख्त के आरोप लगते हैं। उनका यह बयान महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों से पहले उम्मीदवारों को प्रलोभन देने और दबाव बनाने के आरोपों के बीच आया है। उन्होंने कहा कि या तो मौजूदा स्वरूप में ऐसे चुनाव बंद कर दिए जाने चाहिए या फिर उनमें खुले मतदान की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुले ने कहा, मैं चुनाव प्रक्रिया में संरचनात्मक बदलाव के लिए संसद में एक विधेयक पेश करूंगी। चुनावों में खरीद-फरोख्त के आरोप बंद होने चाहिए। सरपंच से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव पारदर्शी होने चाहिए। 18 जून को होने वाले विधान परिषद की 16 सीटों के चुनाव से पहले महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। सुप्रिया सुले ने इस फैसले का समर्थन किया। सुले ने कहा, सभी सहयोगी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद यह फैसला सामूहिक रूप से लिया गया था। खरीद-फरोख्त की आशंकाओं को लेकर व्यापक चिंता थी। हर जगह खरीद-फरोख्त की चर्चाएं हो रही थीं। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से पहले हुई बैठकों में एनसीपी (शरद पवार), कांग्रेस और शिवसेना (उदय बालासाहेब टाकरे) के नेता मौजूद थे। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आलोचना पर सुप्रिया सुले ने कहा कि हर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति अलग होती है। उन्होंने पूछा कि क्या राजनीतिक दलों को खरीद-फरोख्त करने देनी चाहिए। चुनावी सुधारों की अपनी योजना की घोषणा करते हुए बारामती सांसद ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से संसद में एक विधेयक लाएंगी, ताकि अत्यल्प चुनावों में बार-बार लगने वाले खरीद-फरोख्त के आरोपों का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा, एक नागरिक और जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यह विधेयक पेश करूंगी। ऐसे चुनावों में खरीद-फरोख्त के आरोप बंद होने चाहिए।

कर्नाटक सरकार में टला बड़ा संकट?

रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा विवाद सुलझा, शिवकुमार बोले- सब कुछ ठीक हो गया

वाँडस ऑफ प्रतिज्ञा बंगलूरू

कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार बनने के तीन दिन के भीतर पैदा हुआ पहला बड़ा राजनीतिक संकट फिलहाल टल गया है। मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफा की घोषणा के बाद मंचे सियासी घमासान को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने देर रात हुई लंबी बैठक के बाद शांत कर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह परिवार का मामला था और अब सब कुछ सुलझा लिया गया है। विभागों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे रामलिंगा रेड्डी ने भी संकेत दिए कि विवाद खत्म हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने कर्नाटक कांग्रेस के भीतर की खींचतान को जरूर उजागर कर दिया। रामलिंगा रेड्डी ने शुक्रवार को मंत्री पद से



इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। उनकी रेड्डी का दावा था कि उन्हें बंगलूरू विकास नाराजगी विभागों के बंटवारे को लेकर थी। विभाग देने का आश्वासन दिया गया था,

लेकिन बाद में उन्हें जल संसाधन विभाग सौंप दिया गया। इसके बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद सामने आई इस नाराजगी ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी थी। माना जा रहा था कि अगर मामला नहीं सुलझता तो सरकार के भीतर असंतोष और बढ़ सकता था। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार शुकवार देर रात जयनगर स्थित एक निजी हॉटल पहुंचे, जहां उन्होंने करीब छह घंटे तक रामलिंगा रेड्डी से बातचीत की। बैठक देर रात से लेकर शनिवार तड़के तक चली। इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और रेड्डी के करीबी लोग भी शामिल रहे। बैठक के बाद शिवकुमार ने मीडिया से कहा कि यह परिवार का मामला था और अब सब कुछ ठीक हो गया है। उन्होंने कहा कि विभागों के

बंटवारे में गलतफहमी हुई थी, जिसे बातचीत से सुलझा लिया गया है। शिवकुमार ने भरोसा जताया कि सरकार एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि वह और रामलिंगा रेड्डी 1980 से दोस्त हैं और दोनों के बीच मजबूत राजनीतिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं को सम्मान और अवसर दिया गया है तथा आगे भी सब कुछ संतुलित तरीके से चलाया जाएगा। वहीं रामलिंगा रेड्डी ने भी विवाद खत्म होने के संकेत दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस्तीफा वापस लेंगे, तो उन्होंने सिरफ और रेड्डी के करीबी लोग भी शामिल रहे। बैठक के बाद शिवकुमार ने मीडिया से कहा कि यह परिवार का मामला था और अब सब कुछ ठीक हो गया है। उन्होंने कहा कि विभागों के फिलहाल संकट को टाल दिया है।